मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अणुशक्ति कर्मचारी संघ ने 27 जनवरी, 1970 को उनसे भेंट की थी और अपनी मांगें प्रस्तुत की थीं;

(ख) क्या यह सच है कि अणुशक्ति आयोग के सभापति ने सम्बन्धित व्यक्तियों को इस मामले पर विचार करने के लिये बुलाया था; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 27 जनवरी, 1970 को किसी मीटिंग के होने की सूचना मुझे नहीं है । मुझे कर्मचारी संघ की ओर से कोई मांग भी नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग). राजस्थान अणुशक्ति परियोजना कर्मचारी संघ ने एक मांग-पत्र पेश किया है जिसमें सम्मिलित विषय है:— 18-11-1969 को ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, अनुशासन के मामलों को वापिस लेने, कर्मकार अंशदायी भविष्य निधि योजना, यातायात, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, बिजली तथा पानी की सप्लाई की दरें, परियोजना के क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के लिये निशुल्क आवास सुविधा । कर्मचारियों एवं सरकार के प्रतिनिधियों, जिनमें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, की 29 तथा 30 जनवरी, 1970 को हुई एक संयुक्त मीटिंग में इन मांगों पर विचार विमर्श किया गया । 18-11-1969 के लिये वेतन के भुगतान, कर्मकार अंशदायी भविष्य निधि योजना को लागू करने, ट्रांसपोर्ट की दरों, बिजली तथा पानी की दरों से संबंधित मांगों पर विचार विमर्श कर उनके बारे में फैसला किया गया । यह भी निर्णय किया गया कि संयंत्र स्तर की एक संयुक्त परिषद बनाई जाये जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी कठिनाइयों पर समय समय पर विचार करेगी तथा उन मांगों पर भी विचार करेगी जिन पर उपरोक्त मीटिंग में विचार नहीं किया जा सका ।

Thermal Power Station at Ukai in Gujarat.

2573. SHRI MANUBHAI PATEL : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a thermal power station at Ukai so as to be able to utilize the material from coal fields of Madhya Pradesh ;

(b) the details of the project ; and

(c) how long it will take to implement the scheme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) yes, Sir.

(b) and (c). The scheme envisages installation of a coal-based thermal power station at Ukai with four generating units of 120 MW each at an estimated cost of about Rs. 68 crores. The scheme is expected to take about 4-5 years for completion.

रूई का आयात

2574. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिल संघ के अध्यक्ष ने जनवरी, 1970 में सरकार को लिखे गये पत्र में यह मांग की है कि सरकार को विदेशों से रूई और धागे की 5 लाख गांठों का आयात करना चाहिए;

(ख) क्या उसने रूई के मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि की शिकायत भी की है;

(ग) क्या कपड़ा मिल संघ के अध्यक्ष की इच्छा किसानों से सस्ती दर पर रूई खरीदने की है; और

(घ) इस बात के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि किसानों को रूई के उचित मूल्य मिलें क्योंकि उन्हें फसल के समय अपनी रूई बेचनी पड़ती है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). भारतीय सूती

वस्त्र मिल संघ के अध्यक्ष ने दिनांक 8-1-70 के अपने पत्र में रुई की पूर्ति में सुधार हेतु रुई की 2.5 लाख अतिरिक्त गांठों और 2 करोड़ रु. मूल्य के स्टेपल रेशे के आयात की व्यवस्था करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है । पत्र में कहा गया है कि रुई की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में 250 रु. से 300 रु. प्रति कैण्डी की औसत वृद्धि हुई है ।

(ग) प्रत्यक्षत: रुई/स्टेपल रेशे के अतिरिक्त आयात की मांग, रुई की आवश्यकता और पूर्ति की स्थिति के असंतुलन और रुई के मूल्यों में कुछ हद तक असमान्य वृद्धि को देखते हुए की गयी है ।

(घ) 1-9-1967 से रुई के अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की पद्धति समाप्त कर दी गयी है और तभी से, उत्पादक को एक न्यूनतम लाभ अवश्य मिले यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों का एलान किया जाता है और यह आश्वासन भी दिया जाता है कि इन मूल्यों पर बिक्री हेतु रुई की पेशकश होने पर सरकार उसे खरीदने के लिए तत्पर रहेगी ।

महाराष्ट्र में भूमि-हीन सैनिक कर्मचारियों को भूमि का आवंटन

2575. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भूमिहीन ऐसे कितने सैनिक कर्मचारी हैं जिन्हें जनवरी, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक की अवधि में भूमि आवंटित की गई है; और

(ख) उक्त राज्य में भूमि आवंटन के लिये इस समय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं. रं. कृष्ण) : (क) तथा (ख). सूचना प्राप्य नहीं और राज्य सरकारों के साथ लिखा पढ़ी करते इसे इकट्ठा करने में अन्तर्ग्रस्त समय और श्रम प्राप्य हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा ।

Export Trade

2576. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Board of trade at its meeting held in December, 1969 decided that efforts must be made within the next three months to export additional goods worth Rs. 70 crores over and above existing plans if the 7 per cent growth target was to be achieved; and

(b) the details of the efforts made in this direction and with what results ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) A Crash Export Programme has been launched by the Government. The emphasis of the programme is primarily on (1) the speedy removal of obstacles and bottlenecks in the way of export; (2) encouragement for increasing exports from ex-stock and from scheduled production; (3) encouragement for fuller utilisation of idle capacity specifically for export through adequate supply of (i) raw materials whether imported or indigenous and (ii) other essential inputs; (4) endeavouring through State Governments to improve labour-management relation (5) barter deals; (6) expeditious movement at the ports and (7) special marketing efforts by public sector as well as private enterprises. Partly as a result of the Crash Programme and partly due to other factors, the decline in the rate of growth of exports was arrested in December, 1969. Non-traditional products such as engineering goods have responded well the action taken. In the traditional products, the introduction of selected fiscal reliefs proposed under the Budget for 1970-71 and the impetus of the Crash Programme are together expected to generate additional exports in the near future.

Export of Woollen Hosiery through S.T.C.

2577. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that woollen hosiery is exported through State Trading Corporation;